नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 033
दि. 02.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सीएम योगी का जनता दर्शनः बच्चे से बोले सीएम- तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी चीजें हम पर छोड़ दो; हम देख लेंगे

(जीएनएस)।

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की, उनके प्रार्थना पत्र लिए और उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण समयसीमा के भीतर हो, विलंब होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए। सीएम योगी ने कुछ बच्चों से शिक्षा के बारे में भी पूछा और अभिभावकों से कहा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, क्योंकि पढ़ा-लिखा बच्चा ही सशक्त भारत की नींव है।

मुख्यमंत्री जी के समक्ष राजस्व व पुलिस से जुड़े भी कुछ मामले आए। मुख्यमंत्री ने उनका संज्ञान लिया और कहा कि लंबित राजस्व वादों का

समयसीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। छह महीने से अधिक लंबित वादों के कारणों की समीक्षा की जाए। उचित कारण न होने पर भी यदि निस्तारण में विलंब होता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर खुशी लाना शासन-प्रशासन का दायित्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान हो। अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सभी को न्याय और हर पात्र को योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो। जरूरतमंद के चेहरे पर खुशहाली लाना शासन-प्रशासन का दायित्व है।

बेटा! तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो

हापुड़ से एक बच्ची अपने अभिभावक के साथ आई थी। उसने अपने परिवार की माली स्थिति का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि किस क्लास में हो, इस पर बच्ची ने कक्षा-7 बताया और आगे की पढ़ाई में आने वाली बाधाओं का भी जिक्र किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि घर जाओ और सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो। अभिभावक से कहा कि शिक्षित बच्चा ही सशक्त भारत की नींव है। अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे, आप बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें।

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान'

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ करते हुए किसानों को साफ संदेश दिया कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

1 से 30 जून तक देशभर में चलने वाले इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धरती हमारी माता है और इसकी सेहत बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

शाकंभरी मंदिर पहुंचे सीएम योगी, बाढ़ त्रासदी पर सख्त रुख, चौकी इंचार्ज निलंबित

सहारनपुर के शाकंभरी मंदिर में हाल ही में आई बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। दो महिलाओं की मौत हो गई थी। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने के लिए शाकंभरी मंदिर पहुंचे।

(जीएनएस)।

सहारनपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सहारनपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचकर हाल ही में आई बाढ़ और सैलाब से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया और आपदा के दौरान प्रशासनिक तैयारियों व राहत कार्यों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले ही पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए शाकंभरी मंदिर चौकी प्रभारी संजय कुमार को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में संभावित खतरे और सैलाब की आशंका की जानकारी होने के बावजूद समय रहते श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सतर्क नहीं किया गया। सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में लापरवाही को लेकर यह कार्रवाई की गई है।

दो महिलाओं की जान चली गई थी

हाल ही में शाकंभरी क्षेत्र में आए तेज सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। इस हादसे में दो महिलाओं की जान चली गई, जबकि करोड़ों रुपये की संपत्ति और सामान पानी के तेज बहाव में बह गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि प्रशासन समय रहते अलर्ट जारी करता और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करता, तो जान-माल के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था।

सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक

मंदिर परिसर और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू की। बैठक में बाढ़ त्रासदी, राहत एवं बचाव कार्य, कानून-व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों से घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट मांगी है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने के संकेत दिए हैं।

अन्य विभागों के अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी

सूत्रों के अनुसार, चौकी प्रभारी पर हुई कार्रवाई के बाद अन्य विभागों के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे और प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। वहीं, मुख्यमंत्री के निरीक्षण के समय आई आपदा को लेकर चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सूत्रों की माने तो इस आपदा को लेकर लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।

अधिकारियों को योगी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से मजबूत व्यवस्था तैयार की जाए, ताकि श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनका यह दौरा न केवल आपदा प्रबंधन की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका में बहाए करोड़ों, FARA रिपोर्ट से खुली पोल

पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान भारत ने अमेरिका से बीच-बचाव यानी मध्यस्थता की मांग की थी। लेकिन अब अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों से एक अलग तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी रिकॉर्ड बताते हैं कि पाकिस्तान खुद वॉशिंगटन में अपनी पहुंच बढ़ाने और अमेरिकी नीति निमार्ताओं को प्रभावित करने के लिए हर महीने लगभग 1 मिलियन डॉलर यानी करीब 10 लाख डॉलर खर्च कर रहा था।

दिग्विजय सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले- भरोसा है कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा

(जीएनएस)।

नीट विवाद के बीच सोमवार को शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान की रही. समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा देश की व्यवस्था पर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, न ही उनके हितों से कोई समझौता किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि यह विषय राजनीति का नहीं, बल्कि लाखों बच्चों व माता-पिता की चिंता से जुड़ा हुआ है.

इस अहम बैठक में आगामी 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से बात हुई. इसमें पेपर को पूरी तरह सुरक्षित बनाने तथा छात्रों के मन में दोबारा विश्वास जगाने को लेकर कई जरूरी सुझाव दिए गए.

बैठक शुरू होने से पहले समिति

के सदस्यों के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई. इस दौरान सत्तापक्ष के कुछ सांसदों ने सवाल उठाया कि जांच जारी रहने के बीच ऐसी बैठकों की जरूरत क्या है और क्या इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है. इस पर दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि मामला राजनीति का नहीं है. यह लाखों छात्रों तथा अभिभावकों की चिंता से जुड़ा मुद्दा है.

उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और अधिकारियों को 21 जून को होने वाली ठएएळ पुनर्परीक्षा के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दीं. समिति ने यह भी पूछा कि परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित तथा लीक-प्रूफ बनाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं. अधिकारियों ने समिति को बताया कि पेपर सुरक्षा मजबूत करने के लिए इन-हाउस पेपर सेटर्स, शिक्षकों तथा प्रोफेसरों की मदद ली जा रही है. कोशिश यही है कि इस बार किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न बचे.

भारत की आधिकारिक यात्रा पर म्यांमार के राष्ट्रपति , एनएसए डोभाल और जयशंकर के बाद पीएम मोदी से हुई मुलाकात, जानें क्या हुई बात

(जीएनएस)।

नई दिल्ली : भारत और म्यांमार ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही व्यापार, निवेश, संपर्क (कनेक्टिविटी), विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। सोमवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई विस्तृत वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।

म्यांमार की हर मदद को तैयार भारत

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में शांति और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत हर तरह की मदद को तैयार है। उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास के अनुभव साझा करने की भी बात कही। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति की बातचीत व्यापक रही और दोनों देशों ने शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।

उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के लिए एक भरोसेमंद पड़ोसी और संकट

के समय में पहला सहयोगी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की ह्लनेबरहुड फर्स्टह्व, ह्लएक्ट ईस्टह्व और ह्लमहासागरह्व नीतियों के अनुरूप भारत हमेशा म्यांमार का सहयोग करता रहेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे राष्ट्रपति यू मिन

राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का सोमवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात का कार्यक्रम है। वे राजधानी में ह्लद लाइट एंड द लोटसः रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वनह्व नामक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे।

आपको बता दें कि यह म्यांमार राष्ट्रपति की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधियों का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वे मुंबई में व्यापारिक बैठकों और विभिन्न स्थलों का भी दौरा करेंगे।

'8 लाख हस्ताक्षर, 1 करोड़ प्रभावित', CJP प्रमुख ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन का किया ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं का

आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। दीपके का दावा है कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों से एक करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं, जबकि उनकी ऑनलाइन याचिका को अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है।

मध्यप्रदेश में जल्द लागू होगी यूसीसी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता से मांगे सुझाव

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश, समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। एक सरकारी समिति, जिसका नेतृत्व एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कर रहे हैं, विभिन्न समुदायों से सुझाव लेने के लिए जिलों में जा रही है, और एक समर्पित वेबसाइट पर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसका लक्ष्य पारिवारिक और व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत कर अधिकारों और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है।

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यूसीसी के लिए गठित समिति विभिन्न जिलों में जाकर अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों से सुझाव ले रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे सरकार द्वारा शुरू की गई वेबसाइट पर अपने सुझाव अवश्य साझा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक मामलों में अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। समाज और कानून के स्तर पर समानता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना समय की मांग है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि यूसीसी के अध्ययन और सुझावों के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रही हैं। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और विद्वान भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि समिति प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों से संवाद कर रही है तथा उनके सुझाव एकत्रित कर रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार यूसीसी को जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तलाक, पारिवारिक परंपराओं और अन्य सामाजिक-धार्मिक मामलों में अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं के बजाय एक समान व्यवस्था होना आवश्यक है।

अन्नामलाई, मोदी के फायरब्रांड नेता क्या सच में छोड़ेंगे भाजपा?

तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर के. अन्नामलाई चर्चा के केंद्र में हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने की अटकलों पर ऐसा बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल और बढ़ा दी है। चेन्नई से दिल्ली रवाना होते समय जब उनसे पूछा गया कि क्या वह नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने वाले हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा, "दो दिन इंतजार कीजिए, फिर बैठकर बात करेंगे।"

'छात्र अब घरों में झाड़ू पोंछा लगाने लगे', परीक्षाओं में छात्राओं के शानदार नतीजों पर सीएम योगी ने ली चुटकी

(जीएनएस)।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं के मुकाबले छात्रों का रिजल्ट कमजोर होने पर छात्रों की चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि लगता है कि छात्र अब घरों में झाड़ू पोंछा लगाने लगे हैं। लगता है कि कुछ छात्र मोहल्ले में भी झाड़ू लगाने लगे हैं, तभी तो परीक्षाओं में छात्राओं की तुलना में उनके अंक कम आ रहे हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यह बात लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा विभाग की केंद्र एवं राज्यस्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों व प्रधानाचार्यों के सम्मान समारोह में कही।

मां-बाप छात्रों से ज्यादा काम ले रहे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 'हम लोग ये मानते थे कि छात्राएं घर में अपनी माताओं के काम में भी सहयोग करती हैं। लगता है कि अब परिवर्तन आ गया है। छात्र घर में झाड़ू पोंछा ज्यादा लगाने लग गए हैं। या लगता है कि मां-बाप उनसे ज्यादा काम ले रहे हैं। सब्जी लेने के लिए भेजते होंगे। हो सकता है घर और मोहल्ले में भी कुछ झाड़ू लगा रहे होंगे। इसीलिए छात्रों के अंक इतने कम है और छात्राएं मेहनत कर रही हैं और मेरिट में उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया है।'

छात्राओं से प्रेरणा लें छात्र

उन्होंने कहा कि, 'यह एक सुखद लक्षण है। लेकिन छात्रों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि छात्राएं घर में परिवार का सहयोग करते हुए भी अच्छे अंक प्राप्त कर रही हैं, मेरिट में ज्यादा स्थान प्राप्त कर रही हैं, तो छात्र कम से कम उनका ही अनुसरण कर लें।'

बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 'मेरा मानना है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। हम सबके सामने यह इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश बहुत स्पष्ट आ गया है।'

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

10 स्वर्ण समेत 19 पदक: दिखा भारतीय युवाओं का दम; प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स टीम को दी बधाई

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, भारत ने 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा एथलीटों को बधाई देते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन देश की युवा प्रतिभा, दृढ़ता और उत्कृष्टता का प्रतीक है।

भारत ने 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक अपने नाम किए। भारतीय दल ने 10 स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। मेजबान चीन 25 पदकों और 14 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि जापान 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन की देशभर में सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर भारतीय दल को बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा, '22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीतने के लिए भारतीय दल को बधाई। यह शानदार प्रदर्शन हमारे युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है।

मुझे उम्मीद है कि उनकी ये उपलब्धियां आने वाले वर्षों में और अधिक युवा भारतीयों को खेलों की ओर प्रेरित करेंगी।' प्रधानमंत्री के इस संदेश को भारतीय एथलेटिक्स के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

आखिरी दिन भारत ने जीते तीन स्वर्ण पदक

चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। सबसे यादगार प्रदर्शन महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने किया। नीरू पाठक, भूमिका संजय नेहते, तहूरा खातून और सेहनूर बावा की चौकड़ी ने 3:38.07 सेकेंड का समय निकालते हुए नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। यह प्रदर्शन प्रतियोगिता के सबसे बड़े आकर्षणों में शामिल रहा। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में मुस्कान ने 16:53.08 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, वेंकटराम रेड्डी मोगली ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में 1:48.27 सेकेंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

फील्ड इवेंट्स में निश्चय ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 60.10 मीटर का थ्रो कर रजत पदक जीता। यह नया भारतीय अंडर-20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही वह इस वर्ग में 60 मीटर की दूरी पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए।

महिलाओं की 4x100 मीटर रिले टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। काजल हीराभाई वाजा, भावना जी, आरती और निपम ने 45.05 सेकेंड का समय निकालकर भारत को दूसरा स्थान दिलाया।

भविष्य के सितारों ने दिखाई ताकत

इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ पदक जीते, बल्कि कई राष्ट्रीय और चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बनाए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय एथलेटिक्स की नई पीढ़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी इसी विश्वास को मजबूत करता है कि भारत के युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में विश्व स्तर पर देश का नाम और ऊंचा करेंगे।

'नालायक औलादों को समझा लो, वरना...', सूर्या हत्याकांड पर सीएम योगी की चेतावनी- दोस्ती में चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं

(जीएनएस)।

गाजियाबाद। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोमवार को उस समय कड़ा रुख दिखा, जब वे बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कड़े लहजे में कहा, 'चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

सोमवार को बिजनौर के एक कार्यक्रम में गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड को लेकर सीएम योगी ने कहा, 'हम सज्जन के लिए सज्जन हैं और दुर्जन के लिए दुर्जन।'

सीएम योगी ने कहा कि बकरीद पर गाजियाबाद में हिंदू युवक की हत्या की गई लेकिन, इस पर विपक्ष चुप रहा। उन्होंने कहा, 'नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा।'

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, 'गाय को पशु मानने वाले इंसान नहीं है, गाय स्वाभाविक हमारी माता हैं।'

सूर्या पर चाकू से किया था हमला

बता दें कि ईद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या नाम के युवक को चाकू से हमला करके घायल कर दिया गया था। इसके बाद सूर्या की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मऊ: 'प्राइवेट स्कूल कर रहे धन उगाही, सीएम योगी खोलें सरकारी कन्या कॉलेज', मुहम्मदाबाद गोहना में उठी बड़ी मांग

(जीएनएस)।

मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने से गरीब बेटियों की पढ़ाई छूट रही है. प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस और धन उगाही से परेशान स्थानीय जनता, समाजसेवियों और नेताओं ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां तुरंत सरकारी कन्या कॉलेज खोलने की मांग की है, ताकि छात्राओं को सुरक्षित माहौल में बेहतर और मुफ्त शिक्षा मिल सके.

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने के कारण बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र में सरकारी विकल्प न होने से गरीब परिवारों की बेटियां या तो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं या फिर निजी स्कूलों की महंगी फीस के जाल में फंसी हैं. इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और आम जनता ने सुर में सुर मिलाकर यहां तत्काल एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खोलने की मांग उठाई है, ताकि क्षेत्र की बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके.

बीजेपी नेता लाल जी वर्मा ने सीएम योगी को सौंपा ज्ञापन

लोकल 18 से विशेष बातचीत करते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व भाजपा नेता लाल जी वर्मा ने बताया कि मुहम्मदाबाद गोहना में कोई राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने से छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. राजकीय कॉलेज न होने के कारण गरीब तबके के लोग अपनी बेटियों को प्राइवेट विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाते और वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं. यदि यहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खुल जाए, तो उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने में काफी आसानी होगी.

उन्होंने आगे बताया कि इस मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है. सरकार की वर्तमान नीति भी प्रत्येक ब्लॉक में कन्या इंटर कॉलेज खोलने की है. वह खुद अपने राजनीतिक जीवन में हर स्तर पर शासन-प्रशासन के सामने इस राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की मांग को प्रमुखता से उठाते चले आ रहे हैं.

बीजेपी में कौन बनेगा हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय? इन तीनों में रेस शुरू!

निजी स्कूलों की भारी फीस से गरीब छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर

भाजपा नेता लाल जी वर्मा ने जोर देकर कहा कि यदि यहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खुल जाता है, तो बेहद गरीब परिवार की बालिकाओं को भी सही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी. हालांकि, क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज तो खोल दिया गया है, जिससे वहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने में लोगों को सहूलियत हो रही है, लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज (11वीं-12वीं) न होने से गरीब परिवारों की कन्याएं बीच में ही अशिक्षित रह जाती हैं. यदि यह कॉलेज खुल जाए तो यह बड़ी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी.

इसी क्रम में स्थानीय सभासद नंदलाल सोनकर ने बताया कि इस क्षेत्र में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने से जमीनी स्तर पर काफी दिक्कतें आ रही हैं. गरीब परिवार की कन्याएं शिक्षा की मुख्यधारा से बहुत दूर होती जा रही हैं. प्राइवेट स्कूलों में अत्यधिक फीस होने की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राएं पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हैं. इसलिए यहां अविलंब राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खोलना अति आवश्यक हो गया है.

सुरक्षा का संकट और निजी संस्थानों की धन उगाही से जनता त्रस्त

पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉ. धर्म सिंह गौतम ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मुहम्मदाबाद गोहना में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज न होने से तमाम तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं. अक्सर घर से दूर निजी और प्राइवेट संस्थानों में जाते समय छात्राएं रास्ते में किसी न किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना की शिकार हो जाती हैं. ऐसे असुरक्षित माहौल में वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पातीं और सिर्फ एडमिशन लेकर ही स्कूल छोड़ देती हैं. यदि यहाँ सरकारी कन्या इंटर कॉलेज खुल जाए, तो वहां योग्य और चयनित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे बेटियां शिक्षित बनेंगी और अपना भविष्य संवार सकेंगी. पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर घर की कन्या का शिक्षित होना बहुत जरूरी है.

वहीं, स्थानीय नागरिक जितेंद्र यादव ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि सरकारी कॉलेज न होने से छात्राओं को मजबूरी में निजी विद्यालयों में दाखिला लेना पड़ता है, जहां फीस के नाम पर तगड़ी वसूली की जाती है. गरीब परिवारों के पास इतना बजट नहीं होता कि वे इस महंगी पढ़ाई का खर्च उठा सकें, जिसके कारण उनकी बेटियां शिक्षा से महरूम रह जाती हैं. प्राइवेट विद्यालयों में फीस के नाम पर सिर्फ धन उगाही का खेल चल रहा है. यदि यहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खुल जाए, तो आम जनता को इस आर्थिक शोषण से बड़ी राहत मिलेगी और वे अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल में बेहतर शिक्षा दे पाएंगे.

गोंडा में अब दो किमी. से छोटी सड़क बनेगी सीसी, सीएम योगी की अपील के बाद नए तरीक से बन रहा एक्शन प्लान

(जीएनएस)।

गोंडा। तारकोल की किल्लत के चलते अब दो किलोमीटर से कम लंबाई की सभी सड़कें सीमेंट व कंक्रीट से बनाई जाएंगी। यही नहीं डामर बनाने में भी सीटीबी (सीमेंट टेस्ट बेस)व सीटीएसबी (सीमेंट टेस्ट सब बेस) तकनीक इस्तेमाल कर तारकोल की खपत घटाई जाएगी।

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते तारकोल की किल्लत बरकरार है। मार्च में रहा 46 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन का भाव अब 83 हजार रुपये मीट्रिक टन पहुंच चुका है। महंगे मूल्य के बाद भी यह नही मिल पा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने डामर की जगह सीसी रोड बनाने का निर्देश लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को दिया था।

इस समय सड़कों का निर्माण की कार्ययोजना बनाई जा रही है,जिनका निर्माण बारिश के बाद होगा। प्रत्येक विधानसभा से करीब 100 सड़कों के

नवनिर्माण का प्रस्ताव मिला है। सातों विधानसभा क्षेत्रों से मिले 700 सड़कों के निर्माण में एक किलोमीटर से छोटी सड़क लोक निर्माण की जगह दूसरे विभाग बनाएंगे जबकि दो किलोमीटर से कम लंबाई वाली सभी सड़कों को डामर की जगह सीसी (सीमेंट-कंक्रीट) रोड बनाया जाएगा। इससे तारकोल की खपत घटेगी और जलभराव में सड़क के टूटने का डर भी नहीं रह जाएगा।

नई तकनीक से डामर बनाने में घटेगी तारकोल की खपत

यही नही डामर सड़क बनाने में भी अब नई तकनीक का प्रयोग होगा। सड़क बनाने में पत्थर डालने के पूर्व निचली परत में सीटीबी (सीमेंट टेस्ट बेस) या उसके ऊपर दूसरी परत में सीटीएसबी (सीमेंट टेस्ट सब बेस) बनाया जाएगा। इससे डामर की मोटाई कम हो जाएगी, जिससे तारकोल कम लगेगा।

लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब दो किलोमीटर से छोटी सड़क सीमेंट व कंक्रीट से बनेगी। साथ ही डामर में भी तकनीक से तारकोल की खपत घटाई जाएगी।

केजीएमयू दवा घोटाले में यूरोलॉजी विभाग पर बड़ा एक्शन, कर्मचारियों के लखनऊ छोड़ने पर रोक

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दवा वितरण से जुड़े कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है.

(जीएनएस)।

लखनऊः किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में दवा वितरण से जुड़े कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है. प्रशासन ने यूरोलॉजी विभाग में तैनात दवा वितरण कर्मचारियों को तत्काल हटाते हुए सभी कर्मचारियों के लखनऊ से बाहर जाने पर रोक लगा दी है. दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों से रिकवरी के साथ सेवा समाप्ति की भी तैयारी है.

क्या थी शिकायतः KGMU प्रशासन को शिकायत मिली थी कि यूरोलॉजी विभाग के दवा काउंटर पर संविदा कर्मियों की मिलीभगत से दवाओं की अनियमित बिक्री और वितरण में गड़बड़ी की जा रही है. मामले की गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने जांच समिति गठित की. जांच शुरू होते ही यूरोलॉजी विभाग के दवा वितरण से जुड़े संविदा कर्मियों को काउंटर से हटा दिया गया है.

रिकवरी की जाएगीः KGMU प्रवक्ता

डॉ. केके सिंह ने बताया कि जांच समिति आज शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों से आर्थिक रिकवरी की जाएगी और उनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं.साथ ही, जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी को लखनऊ छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ या फरारी की आशंका न रहे.

KGMU में यह पहला मामला नहीं है जब दवा और उपकरणों की खरीद-वितरण पर सवाल उठे हों. इससे पहले भी अस्पताल में 119 करोड़ रुपये की दवाएं बिना गुणवत्ता जांच के मरीजों को देने और ढढढ मॉडल पर मशीनों के संचालन में अनियमितता के आरोप सामने आ चुके हैं.यूरोलॉजी विभाग में ढढढ मॉडल पर करीब 20 साल से अल्ट्रासाउंड मशीनें चल रही हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन की निगरानी कमजोर रहने के आरोप लगते रहे हैं.

हाल ही में यूरोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड के दौरान महिला मरीज से छेड़छाड़ के मामले में एजेंसी के जरिए तैनात डॉक्टर और ड्यूटी पर मौजूद वार्ड आया को भी नौकरी से हटाया गया था. इन लगातार घटनाओं के बाद KGMU प्रशासन अब सख्त रुख अपनाते हुए सिस्टम में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है.

प्रशासन का कहना है कि मरीजों को मिलने वाली दवाओं और इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

लखनऊ में आईटी सिटी का बढ़ेगा दायरा:छूटी जमीनों को भी योजना में शामिल करेगा LDA; 2 लाख परिवार को मिलेगा घर

(जीएनएस)।

लखनऊ में प्रस्तावित आईटी सिटी योजना का दायरा अब और बढ़ेगा। करीब 3490 एकड़ में विकसित की जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब उन जमीनों को भी शामिल किया जाएगा, जो पहले अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर रह गई थीं। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अलग से भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

योजना क्षेत्र से सटी और पूर्व में विभिन्न कारणों से छूटी हुई जमीनों को चिह्नित किया जा रहा है। इनमें अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना के लिए आरक्षित कुछ भूमि भी शामिल है। एलडीए का मानना है कि भविष्य में विकास कार्यों में किसी

तरह की बाधा न आए, इसलिए योजना की सीमा से सटे किसी भी गाटे को बाहर नहीं छोड़ा जाएगा।

इन गांवों से लगी जमीन भी शामिल की जाएगी

योजना विस्तार के तहत सोनई कंजेहरा, पहाड़नगर टिकरिया, परेहटा और सिकंदरपुर अमोलिया समेत कई गांवों की सीमा से लगी भूमि को शामिल करने की तैयारी है। संबंधित गांवों के गाटावार अभिलेख और नक्शे उपलब्ध होने के बाद अधिग्रहण प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

एलडीए के अर्जन विभाग ने मुख्य नगर नियोजक समेत संबंधित अधिकारियों से गाटावार डीपीआर और भूमि विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। दस्तावेज मिलने के बाद छूटी हुई जमीनों के अधिग्रहण का अलग प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि आईटी सिटी को एकीकृत रूप से विकसित करने के लिए पूरी परिधि को योजना में शामिल करना जरूरी है।

विधि कोर्सों में थ्योरी और इंटरनल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक वाले होंगे पास, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लागू की नई व्यवस्था

(जीएनएस)।

लखनऊ। बार काउंसिल आफ इंडिया के मानकों के अनुरूप उत्तीर्ण होने के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी को किसी भी विषय में पास होने के लिए मुख्य लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन दोनों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

बल्कि थ्योरी और इंटरनल दोनों के अंकों को मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भी विद्यार्थी को उस विषय में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, पूरे सेमेस्टर के सभी विषयों को मिलाकर विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक 45 प्रतिशत या उससे अधिक होने अनिवार्य हैं।

कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने कहा कि थ्योरी और इंटरनल मिलाकर 40 प्रतिशत पर पास होने का नया नियम और 75:25 की नई प्रणाली विद्यार्थियों

को तनावमुक्त करेगी। प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव की ओर से जारी सूचना के अनुसार लवि ने एलएल.बी. (त्रिवर्षीय) और पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रविधानों को लागू करने की आधिकारिक घोषणा की है।

तय हुआ कि दोनों कोर्सों के सभी विद्यार्थियों को विषम से सम सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इससे सैकड़ों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और सत्र भी पूरी तरह नियमित बना रहेगा।

मूल्यांकन पद्धति में बड़ा बदलाव

पूर्व में लागू लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था, जो पहले 90 और 10 के अनुपात में विभाजित थी, उसे संशोधित कर दिया गया है। अब मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 75 प्रतिशत अंक और आंतरिक मूल्यांकन (असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस) के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल 100 अंक के संयुक्त मूल्यांकन में से विद्यार्थियों को पास होने के लिए 40 अंक लाने होंगे।

संशोधित मार्कशीट और परीक्षा फार्म की सूचना : परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अनुसार, प्रथम सेमेस्टर के विधि विभाग की संशोधित मार्कशीट इन नए नियमों के आधार पर शीघ्र ही जारी की जाएगी। मार्कशीट जारी होने के तुरंत बाद ही सभी पात्र छात्र-छात्राएं आगामी सम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भर सकेंगे।

पंजाब में कैसे बना अकाली दल का दबदबा? कांग्रेस को बाहर करने वाली पार्टी ने क्यों खोया जनाधार

(जीएनएस)।

भारतीय राजनीति के इतिहास में क्षेत्रीय दलों का उभार और पतन हमेशा से बेहद दिलचस्प रहा है। पंजाब की राजनीति की कहानी में अगर किसी एक क्षेत्रीय दल ने सबसे गहरी छाप छोड़ी है, तो वह है शिरोमणि अकाली दल। एक समय ऐसा था जब पंजाब की राजनीति कांग्रेस बनाम अकाली दल के इर्द-गिर्द घूमती थी।

दिसंबर 1920 में एक धार्मिक जनसभा से उपजे इस दल का सफर सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा।आधी सदी से भी अधिक समय तक पंजाब ने दोतरफा चुनावी मुकाबला देखा एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और दूसरी तरफ अकाली दल (बाद में भाजपा के साथ गठजोड़)।

'किस्सा कुर्सी दा' के इस एपिसोड में कहानी सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल की, जिसने सिख राजनीति को दिशा दी, कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी, कई बार सत्ता पर कब्जा किया और फिर धीरे-धीरे अपना जनाधार खोती चली गई।

जम्मू-कश्मीर की 'नेशनल कॉन्फ्रेंस' (1939) और तमिलनाडु की 'द्रमुक' (1949) से भी पुरानी राजनीतिक विरासत समेटे शिरोमणि अकाली दल का गठन दिसंबर 1920 में हुआ था। मूल रूप से यह एक 'कैडर-आधारित' और वैचारिक आंदोलन था, जिसे सिख समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने का जनादेश मिला था। उस समय गुरुद्वारा सुधार आंदोलन अपने चरम पर था और अकाली दल इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरा।

अकाली दल ने खुद को हमेशा गुरुद्वारों और सिखों की सर्वोच्च संस्था का रक्षक माना। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने आजादी के बाद पंजाब का भूगोल, डेमोग्राफिक और सियासी भविष्य तय किया। लेकिन स्थापना के बाद से ही यह दल कई बार आंतरिक गुटबाजी का शिकार हुआ। लेकिन जब-जब पंथ पर संकट आया, ये गुट एकजुट भी हुए।

विभाजन से पहले औपनिवेशिक पंजाब में सिखों की आबादी महज 15% थी। इस कारण अकाली दल उस दौर में केवल 'प्रतिनिधित्व' की राजनीति करता था। लेकिन 1947 में विभाजन के बाद जब पंजाब की सीमाएं बदलीं, तो अकाली दल ने भारतीय संघ के भीतर ही एक सिख-बहुसंख्यक राज्य यानी 'पंजाबी सूबा' की मांग को लेकर एक बड़ा भाषाई और धार्मिक आंदोलन छेड़ दिया।

साल 1966 में जब पंजाब की सीमाएं दोबारा खींची गईं और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश अलग हुए, तब पंजाब एक सिख-बहुसंख्यक राज्य बना। इसके बाद से ही राज्य की सियासत कांग्रेस और अकाली दल के इर्द-गिर्द सिमट गई।

बात 1966 की है जब पंजाब की राजनीति लगभग दो ध्रुवों में बंट गई। एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ अकाली दल। लेकिन समस्या यह थी कि कांग्रेस केवल हिंदू वोटों तक सीमित नहीं थी। पार्टी को बड़ी संख्या में सिख मतदाताओं का भी समर्थन मिलता था। कांग्रेस हर चुनाव में बड़ी संख्या में सिख उम्मीदवार उतारती थी और ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में उसकी मजबूत पकड़ थी। यही वजह रही कि अकाली दल को कई बार मजबूत जनाधार होने के बावजूद पूर्ण बहुमत हासिल करने में कठिनाई होती थी।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

प. बंगाल में लोकतंत्र पर आंच

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिसा और आरोप-प्रत्यारोप के चक्र में पंस गई है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनजा पर स्थानीय लोगों द्वारा अंडे, पत्थर और जूते पेंकने की घटना ने न केवल राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि अस्पतालों की निष्पक्षता और राजनीतिक सहिष्णुता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। यह घटना उस समय हुई जब अभिषेक बनजा हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद कथित टीएमसी कार्यकताओं पर हुए हमलों के शिकार परिवारों से मिलने पहुंचे थे। खासतौर पर टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम था। वीडियो पुटेज में देखा गया कि उनके काफिले पर भीड़ ने हमला बोल दिया, नारे लगाए गए "चोर-चोर" और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर निकालना पड़ा। अभिषेक की शर्ट फटी हुई थी और वे भावुक नजर आए। अभिषेक बनजा ने इसे "पूर्व नियोजित हमला" करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पत्थर उनकी आंख के पास से गुजरा और अगर हेलमेट न होता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। टीएमसी ने इसे बीजेपी समर्थकों द्वारा कराए गए हमले बताया और कहा कि नई सत्ता में विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पाटा नेताओं ने कहा कि यह "जनता का गुस्सा" था, जो 15 साल के तृणमूल शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार, हिसा और तानाशाही से त्रस्त है। भाजपा का तर्व है कि टीएमसी चुनाव हारने के बाद पोस्ट-पोल हिसा पैला रही है और ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को राजनीतिक रंग दे रही है। चुनावी परिवर्तन का संदर्भ इस घटना को समझने के लिए 2026 के विधानसभा चुनावों का परिप्रेक्ष्य जरूरी है। भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया - लगभग 207 सीटें, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गईं। ममता बनजा सहित कई टीएमसी के मंत्री चुनाव हार गए। यह 15 साल के टीएमसी शासन का अंत था, जिसमें भ्रष्टाचार, सिंगूर-नंदीग्राम की यादें, संदेशखाली जैसे मामले और राजनीतिक हिसा के आरोप लगते रहे। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी पर टीएमसी कार्यकताओं पर हमलों के आरोप लग रहे हैं, जबकि टीएमसी पर पुराने मामलों का बदला लेने के आरोप। बंगाल में राजनीतिक हिसा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से नई नहीं है। वामपंथी शासन, फिर टीएमसी और अब बीजेपी - हर बदलाव के साथ हिसा के आरोप-प्रत्यारोप चले आए हैं। अस्पताल विवादः नई बहस घटना के बाद अभिषेक बनजा को कोलकाता के बेल व्यू और अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। यहीं से विवाद और गहरा गया। ममता बनजा ने आरोप लगाया कि अस्पतालों पर "ऊपर से दबाव" था। उन्होंने दावा किया कि वुछ अस्पताल उन्हें भता करने से हिचकिचा रहे थे, डॉक्टरों को धमकियां मिल रही थीं और प्राथमिक उपचार में देरी की जा रही थी। ममता ने कहा कि यह केवल हमला नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ भी राजनीति है। हालांकि, अस्पतालों की रिपोर्ट्स अलग कहानी बयां करती हैं। डॉक्टरों ने चोटों को "सतही" बताया। छाती पर हल्की खरोंच के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई। अभिषेक पूरी तरह होश में थे, बोल रहे थे और भता की जरूरत नहीं बताई गई। उन्हें बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। टीएमसी ने इन रिपोर्ट्स पर सवाल उठाए और कहा कि दबाव के कारण सही जांच नहीं हो पाई। यह विवाद स्वास्थ्य संस्थाओं की स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यदि राजनीतिक दबाव का आरोप सही है, तो यह चिंताजनक है। लेकिन यदि यह अतिरंजित है, तो अस्पतालों और डॉक्टरों की गरिमा पर हमला है। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया : राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने हमले की निदा की और राजनीतिक हिसा पर चिंता जताई। टीएमसी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। बीजेपी का पलटवार था कि टीएमसी जब सत्ता में थी, तब विपक्षी कार्यकताओं, पत्रकारों और आम लोगों पर किस तरह अत्याचार हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। हिसा का चक्र तोड़ना होगा अभिषेक बनजा प्रकरण कई सवाल उठाता हैः . राजनीतिक मतभेदों को हिसा में बदलने की संस्वृति कब खत्म होगी? . सत्ता बदलने पर क्या हर बार बदले की भावना हावी हो जाएगी?

अनजाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को अजेय बनाने में मदद

(जीएनएस)।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा का बेबाक विश्लेषणः कैसे गांधी परिवार की राजनीतिक गलतियों और दिशाहीनता ने अनजाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को अजेय बनाने में मदद की है।

कांग्रेस आज भी एक पारिवारिक कंपनी बनी हुई है, जिसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके पास अनुशासन, गंभीरता और अनुभव की भारी कमी है।

साल 2024 के आम चुनावों के तुरंत बाद, मेरी मुलाकात कांग्रेस के एक युवा विधायक से हुई। उन्होंने मुझसे अपने नेता राहुल गांधी के लिए पांच सुझाव मांगे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही सलाह है; और वह यह कि प्रियंका गांधी को वायनाड से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके साथ ही मैंने यह भी जोड़ दिया था कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' ने उनकी साख बढ़ाने में काफी मदद की। इस यात्रा ने उन्हें आम जनता के एक जमीनी नेता के रूप में पेश किया। हालांकि, चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने खुद को फिर से एक पारिवारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया, जिससे उस यात्रा से मिले सभी फायदे बेकार हो गए।

प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट से जीत दर्ज की, जो उनके लिए उतनी ही सुरक्षित सीट है जितनी अमित शाह के लिए गांधीनगर। इसके बाद उन्होंने बड़े गर्व के साथ भाषण दिया कि कैसे वह और उनके भाई देश को एकजुट कर रहे हैं, जहां वह दक्षिण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और उनके भाई उत्तर का।

इसके बाद, संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर होने वाली संसदीय बहस के लिए कांग्रेस ने प्रियंका को प्रमुख वक्ता के रूप में चुना। यह फैसला काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि यह उनकी अपनी ही दादी थीं जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान को कमजोर करने का काम किया था।

इस बीच, आम चुनावों में कांग्रेस को मिली 99 सीटों ने राहुल गांधी के इर्द-गिर्द मौजूद चापलूसों का उत्साह बढ़ा दिया। उन्होंने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि राहुल अब प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हैं। दिल्ली के उन बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने भी इन दावों को हवा दी, जिनकी सत्ता-विरोधी छवि उनके गलत आकलन के कारण धुंधली पड़ गई थी और शायद वे राजनीतिक गुरु बनने के लालच में ऐसा कर रहे थे।

समय से पहले मिली खुशी

दो साल बाद, हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह खुशी कितनी जल्दबाजी में मनाई गई थी। केरल जैसी एकाध राज्य इकाई को छोड़ दें, जो व्यवस्थित है और कभी-कभार विधानसभा चुनाव जीत सकती है, तो देश के ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस ने लगातार अपना जनाधार खोया है।

भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में स्वाभाविक सत्ताधारी पार्टी बन गई है, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। राहुल गांधी पार्टी के इस पतन को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। 'द प्रिंट' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जब 2008 के आसपास राहुल ने कांग्रेस में औपचारिक नेतृत्व संभाला था, तब से लेकर अब तक देश भर में कांग्रेस विधायकों की संख्या लगभग आधी हो गई है। यह आंकड़ा 1,204 से गिरकर 676 पर आ गया है।

मैंने राहुल गांधी से मुलाकात की है और उनके साथ पत्राचार भी किया है और मैं जानता हूं कि वह एक अच्छे इंसान हैं। अगर यह थोड़ी-बहुत जान-पहचान न भी होती, तब भी मुझे उनके प्रति सहानुभूति होती। इसकी वजह उनके जीवन की व्यक्तिगत त्रासदियां हैं और यह सच्चाई भी है कि 55 साल की उम्र में भी वह अपनी मां की इच्छाओं के साधन मात्र बने हुए हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने सोनिया गांधी के निर्देश पर राजनीति में कदम रखा और आज भी उन्हीं के इशारे पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं।

हालांकि, जब बात गणराज्य के भविष्य की हो, तो इंसान को अपनी बात सीधे और बिना किसी लाग-लपेट के कहनी पड़ती है। राहुल गांधी भले ही कितने ही अच्छे इंसान हों, लेकिन जो लोग बीजेपी के नफरत भरे मौजूदा शासन को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं, उन्हें अब राहुल गांधी को अपनी मुख्य उम्मीद के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए।

नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी में अनुशासन, गंभीरता और एक ठोस राजनीतिक अनुभव का पूरी तरह अभाव है। जब वह भारत के चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये जैसा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते भी हैं, तो उसे लगातार और मजबूती से आगे नहीं बढ़ाते। अक्सर देखने में आता है कि 'वोट चोरी' पर एकाध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वह यूरोप या लैटिन अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते हैं।

सच तो यह है कि राजनीति में अपने 22 साल के करियर में, राहुल गांधी ने केवल 'भारत जोड़ो यात्रा' के कुछ महीनों के दौरान ही वह केंद्रित और कड़ी मेहनत दिखाई, जो बीजेपी के नेता हर समय करते हैं। आजकल, उनके राजनीतिक दखल ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' तक ही सीमित रहते हैं। इन पर तुरंत ढेरों लाइक्स तो मिल जाते हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही लोग उन्हें भूल भी जाते हैं।

दिखावटी राजनीति

राहुल गांधी की गंभीरता की कमी उनके राजनीतिक दिखावे में भी साफ नजर आती है। उनकी यह भोली सोच है कि मछुआरों के साथ तालाब में कूदने या शेफ के साथ रसोई में जाने से उनकी पार्टी को वोट मिल जाएंगे। राजनीतिक अनुभव की यह कमी इस बात से भी झलकती है कि उन्होंने कभी कोई असली नौकरी नहीं की।

कोई नहीं जानता कि 2004 में सांसद बनने से पहले राहुल गांधी के पास क्या रोजगार था। जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) दस साल तक सत्ता में रही, तब भी उन्होंने कोई मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे में भारतीय मतदाता उन पर इस विशाल और विविधतापूर्ण देश का एक प्रभावी प्रधानमंत्री बनने का भरोसा क्यों करें, वह भी तब जब दुनिया भर में भू-राजनीतिक चुनौतियां लगातार खतरनाक होती जा रही हैं?

अंततः, राहुल गांधी में अपनी पुरानी गलतियों से न सीख पाने की एक बड़ी कमी है। 2019 में 'चौकीदार चोर है' का अभियान उन पर बुरी तरह भारी पड़ा था। इसके बावजूद, वह शासन की विफलताओं या जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री पर हमले करना (उन्हें कायर, समझौतावादी आदि कहना) जारी रखते हैं।

कांग्रेस के भीतर कई लोग इन आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन गांधी परिवार के प्रति जीवन भर के समर्पण के कारण, उनका मानना है कि राहुल की जगह उनकी बहन को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाना चाहिए। उन्हें अब यह अहसास हो गया है कि राहुल नए नेहरू नहीं बन सकते, इसलिए वे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रियंका नई इंदिरा साबित होंगी।

यह सच है कि हिंदी भाषा में भाषण देने के मामले में प्रियंका अपने भाई से कहीं बेहतर हैं और भारत की एक बड़ी आबादी इस भाषा को समझती है। हालांकि, वह भी वंशवाद के उस भारी बोझ तले दबी हैं। हो सकता है कि मतदाताओं को बूथ तक खींच लाने में वह अपने भाई से भी कम सफल रहें। जब 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका ने पहली बार कांग्रेस के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था, तब पार्टी का वोट शेयर केवल 2.27% रहा था।

वंशवाद का विशेषाधिकार

वैसे, हाल के विधानसभा चुनावों से एक ऐसा सबक भी मिला है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। इन चुनावों के नतीजे वंशवाद के विशेषाधिकार के खिलाफ एक स्पष्ट नकारात्मक टिप्पणी थे। असम में तरुण गोगोई के बेटे के कांग्रेस प्रचार का नेतृत्व करने से बीजेपी को फायदा हुआ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा अपने भतीजे अभिषेक को बढ़ावा देने से भी बीजेपी को लाभ मिला। तमिलनाडु में स्टालिन द्वारा अपने बेटे उदयनिधि को आगे बढ़ाने से विजय को मदद मिली और केरल में विजयन द्वारा अपने दामाद को बढ़ावा देने से कांग्रेस को फायदा हुआ। बेशक, इन चुनावी नतीजों के पीछे कई अन्य कारण भी थे, लेकिन यह निश्चित रूप से उनमें से एक बड़ा कारण था।

कांग्रेस के 'प्रथम परिवार' की इन आलोचनाओं का मतलब यह कतई नहीं है कि मैं मौजूदा शासन का समर्थन कर रहा हूं। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से लिखे गए अपने कई लेखों में, मैंने इस बात का दस्तावेजों के साथ जिक्र किया है कि कैसे इस सरकार ने सार्वजनिक संस्थानों को खोखला किया है। इसने प्रेस और न्यायपालिका को डराया है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्रूरता की है, एक त्रुटिपूर्ण विदेश नीति अपनाई है, भारतीय विज्ञान को नुकसान पहुंचाया है, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया है और हमारे जंगलों, मिट्टी, पानी तथा हवा को तबाह किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मई 2014 से भारतीय गणराज्य के इस पतन के मुख्य सूत्रधार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी बीजेपी हैं। लेकिन अब यह भी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि मोदी और शाह को सत्ता हासिल करने और उसे मजबूत करने में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके इर्द-गिर्द मौजूद चापलूसों ने (जाने या अनजाने में) उनके मददगारों की भूमिका निभाई है।

मुझे अपनी बात निराशाजनक मोड़ पर खत्म नहीं करनी चाहिए। फिलहाल, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अजेय नजर आती है। लेकिन हंगरी में विक्टर ओर्बन और फिडेस पार्टी भी ऐसी ही दिखती थी। फिर भी उन्हें एक बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति पीटर मग्यार और उनकी नई टिसा पार्टी ने शानदार तरीके से सत्ता से बेदखल कर दिया।

चुनाव से दो साल पहले, मग्यार ने बिना थके पूरे देश की यात्रा की। वह छोटे शहरों और यहां तक कि गांवों में भी गए ताकि उस सत्तावादी नेता के खिलाफ अपना पक्ष रख सकें जिसने हंगरी को चलाया और बर्बाद कर दिया था। मग्यार ने वामपंथी, उदारवादी और मध्य-दक्षिणपंथी सहित सभी विपक्षी दलों का एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए जी-तोड़ मेहनत की। उनका एक नया चेहरा होना, भ्रष्टाचार या वंशवाद के दाग से मुक्त होना और उनकी कड़ी मेहनत, यह सब उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई।

जैसा कि एक हंगेरियन संपादक ने फाइनेंशियल टाइम्स में मग्यार के बारे में कहा थाः ह्लवह बेहद जुनूनी हैं। दूसरों के पास साधन हैं, लेकिन उन्होंने मैदान में उतरकर सारी जमीनी मेहनत की।ह्व अफसोस की बात है कि राहुल या प्रियंका गांधी के बारे में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता।

यह पूरी तरह से संभव है कि मोदी की बीजेपी के चारों ओर जो अजेयता का आभामंडल अभी दिख रहा है, वह आने वाले वर्षों में टूट जाए। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र बदहाली में है; नीट (ठएएळ) घोटाला इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। केंद्र सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की कीमतें अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो रुपये की भारी गिरावट, पूंजी के पलायन और रोजगार पैदा करने में विफलता के रूप में सामने आ रही हैं।

2029 के आम चुनाव की तैयारियों के बीच, अधिक से अधिक हिंदुओं को यह अहसास हो सकता है कि मुसलमानों के प्रति नफरत किसी भी तरह से जीवन यापन की बढ़ती लागत, सम्मानजनक रोजगार की कमी या उनके बच्चों के अनिश्चित भविष्य के खतरे की भरपाई नहीं कर सकती।

वास्तव में, राजनीतिक व्यंग्य की बढ़ती लोकप्रियता, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी (उखढ) के मीम्स की सफलता, यह दशार्ती है कि कई युवा भारतीयों ने सत्ताधारी पार्टी के झूठ और प्रोपेगेंडा की सच्चाई को समझना शुरू कर दिया है। बीजेपी यह बात जानती है, इसीलिए सीजेपी के अभिव्यक्ति के माध्यमों को बंद करने की हताश कोशिशें की जा रही हैं।

जब यह मोहभंग और गहरा होगा, तो इसे एक प्रभावी राजनीतिक चुनौती का रूप कौन देगा? कौन सा नेता, या नेताओं का समूह, मौजूदा सरकार की विफलताओं की परतें उधेड़कर और आर्थिक व सामाजिक सुधार के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम पेश करके देश भर के मतदाताओं को प्रेरित कर सकता है? उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह पूरी तरह से असंभव लगता है कि यह काम गांधी भाई-बहनों में से कोई एक या दोनों मिलकर कर सकते हैं।

जी एंटरटेनमेंट ने खरीदे 2026 से 2034 तक के भारतीय प्रसारण अधिकार

(जीएनएस)।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फीफा के 39 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े टूनार्मेंट जैसे फीफा विश्व कप 2026, फीफा महिला विश्व कप 2027 और फीफा विश्व कप 2030 शामिल हैं, और यह समझौता 2026 से लेकर 2034 तक लागू रहेगा, जिससे अगले लगभग 8 साल तक भारत में फीफा फुटबॉल का बड़ा प्रसारण मंच जी एंटरटेनमेंट बनने जा रहा है।

फुटबॉल के चाहने वालों के लिए आने वाला समय काफी खास होने वाला है, क्योंकि बड़े टूनार्मेंट अब भारत में और आसानी से देखे जा सकेंगे। इसी बीच जी एंटरटेनमेंट ने

फीफा के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं। इस नए समझौते के तहत जी की फीफा कवरेज की शुरूआत 11 जून 2026 से होगी, जब फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होगा, और भारत में दर्शक यह सभी मैच जी के नए खेल चैनलों पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकेंगे।

खेल प्रसारण में बड़ा निवेश

जी एंटरटेनमेंट का यह कदम भारत में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उठाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों की दर्शक संख्या बढ़ी है, डिजिटल माध्यमों पर दर्शकों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है और यूरोपीय फुटबॉल लीगों के प्रति रुचि भी काफी बढ़ी है। कंपनी का मानना है कि वह ऐसे खेल अधिकारों में निवेश कर रही है जिनका भविष्य में बड़ा विस्तार और महत्व है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयनका ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों को भारतीय दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों को जोड़ता है।

पीएम मोदी से मिले भजनलाल, बढ़ीं सियासी अटकलें

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक को राजस्थान की राजनीति और भाजपा संगठन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. हाल ही में राजस्थान भाजपा में संगठन महामंत्री की नियुक्ति हुई है, वहीं राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द होने की संभावना है. इसके अलावा लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं जारी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश सरकार के कामकाज, संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं और भाजपा दो सीटों पर जीत की स्थिति में है. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित पिचवाई चित्रकला भेंट की. बैठक के बाद भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत@2047 के विजन और राजस्थान के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की.

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक को राजस्थान की राजनीति और भाजपा संगठन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब प्रदेश भाजपा में हाल ही में संगठन महामंत्री

की नियुक्ति हुई है, राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा निकट है और लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ संगठनात्मक मजबूती, आगामी राजनीतिक रणनीति और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी. पिछले तीन महीनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री मोदी से यह तीसरी मुलाकात है. ऐसे में इस बैठक को राजस्थान में आने वाले समय के राजनीतिक फैसलों से जोड़कर देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री की यह मुलाकात आगामी राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी अहम मानी जा रही है. राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं. विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा दो सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एक सीट पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा मौका मिल सकता है. वहीं दूसरी सीट के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और उद्योगपति नरसी कुलहरी के नाम चर्चा में हैं. संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ फीडबैक साझा किया. माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में भाजपा राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है. यही वजह है कि इस मुलाकात को टिकट चयन की प्रक्रिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक सुंदर पिचवाई पेंटिंग भेंट की. पिचवाई राजस्थान की विश्वप्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला शैली है, जिसकी उत्पत्ति नाथद्वारा से मानी जाती है. यह कला मुख्य रूप से भगवान श्रीनाथजी और भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, रास उत्सव, गोवर्धन पूजा और धार्मिक प्रसंगों को दर्शाने के लिए जानी जाती है.

कपड़े पर हाथ से बनाई जाने वाली इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों, सूक्ष्म ब्रश वर्क, बारीक रेखांकन और समृद्ध राजस्थानी सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. परंपरागत रूप से पिचवाई चित्र मंदिरों में श्रीनाथजी की प्रतिमा के पीछे सजाए जाते थे. आज यह कला राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है और देश-विदेश में इसकी विशेष मांग है. मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को भेंट की गई यह पेंटिंग राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कृष्ण भक्ति का प्रतीक मानी जा रही है.

मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा, महिला, किसान और अंत्योदय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्पण तथा विकसित भारत@2047 के निर्माण के लिए उनका विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणादायी है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह, आत्मीय जुड़ाव और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता प्रेरणा का स्रोत है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान आधारभूत संरचना, निवेश, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है.

उनका मार्गदर्शन और सहयोग विकसित राजस्थान के संकल्प को निरंतर शक्ति प्रदान कर रहा है. राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही इस मुलाकात के बाद अब राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा, संगठनात्मक बदलाव और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

पाकिस्तान को मिल गई टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी, भारतीय टीम खेलने नहीं जाएगी, आईसीसी ने की घोषणा

(जीएनएस)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने साल 2028 में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए अपने रोडमैप का ऐलान कर दिया है। इस बड़े टूनार्मेंट की मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को सौंपा गया है। घरेलू मैदान पर होने वाले इस इवेंट को लेकर पड़ोसी देश में काफी उत्साह है।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव भी सामने आया है। भारतीय महिला टीम के सभी मुकाबले पाकिस्तान से बाहर किसी न्यूट्रल (तटस्थ) वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी ने यह कदम हाइब्रिड मॉडल की नीति के तहत उठाया है, ताकि बिना किसी बाधा के टूनार्मेंट पूरा हो सके।

यह पहला मौका नहीं है जब सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से ऐसा फैसला लिया गया हो। इससे पहले पुरुषों की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी भारत-पाकिस्तान मैचों के लिए इसी तर्ज पर न्यूट्रल ग्राउंड फॉर्मूला अपनाया गया था। वैश्विक संस्था ने इवेंट को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया है।

प्रतियोगिता के प्रारूप की बात करें तो 2028 के इस महाकुंभ में कुल 12 टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ेंगी। टूनार्मेंट में सीधे प्रवेश के लिए आईसीसी ने कड़े नियम बनाए हैं, जिसके तहत कुल 10 टीमों को सीधे ग्रुप स्टेज में जगह दी जाएगी।

इस सीधी एंट्री में पिछले टी20 विश्व कप की शीर्ष आठ टीमें शामिल होंगी। इसके साथ ही मेजबान होने के नाते पाकिस्तान को डायरेक्ट टिकट मिलेगा, जबकि बची हुई जगह रैंकिंग के आधार पर तय होगी। बाकी बची दो टीमों का फैसला एक ग्लोबल क्वालिफायर टूनार्मेंट के जरिए किया जाएगा।

यह तो साफ हो गया कि टीम इंडिया के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे लेकिन स्थान के बारे में खुलासा इवेंट के समय पता चलेगा। इसमें अभी काफी समय है। संभवतः टीम इंडिया का वेन्यू यूएई के किसी स्टेडियम में हो सकता है। भारत में महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में आयोजित हुए थे।

कौन हैं ये दो विधायक? जिन्हें ममता बनर्जी ने टीएमसी से किया निष्काषित

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा से मिली करारी हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अंदर लगातार उठापटक जारी है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने दो विधायकों, संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी, को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया।

(पार्टी ने दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और संगठन के हितों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई को पार्टी अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

टीएमसी विधायक संदीपन साहा उन करीब 60 विधायकों में शामिल थे जो ममता बनर्जी द्वारा कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में नहीं पहुंचे। बड़ी संख्या में विधायकों की अनुपस्थिति के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि अधिकांश विधायक अपने क्षेत्रों में हिंसा के विरोध से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त थे और उन्होंने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी

1 जून को जारी निष्कासन नोटिस में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि दोनों विधायक पार्टी द्वारा नामित होने के बावजूद अधिकृत नेतृत्व की ओर से बुलाई गई बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे। पार्टी के अनुसार, यह व्यवहार संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ था और नेतृत्व के निदेशों की अवहेलना है।

सीएम योगी की फटकार के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी बने गौतमबुद्ध नगर के नए सीएमओ

(जीएनएस)।

नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किए गए हैं।

शासन में चिकित्सा अनुभाग के विशेष सचिव ने बहराइच के डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी को गौतमबुद्ध नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं सीएमओ रहे डॉ. नरेंद्र कुमार को लखनऊ महानिदेशालय में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है।

पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी खुद सभी विभागों में शासन की कल्याणकारी योजनाएं और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि दो दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनपद की खराब स्थिति पर सीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई थी। यही नहीं, विभाग में उच्च अधिकारियों के ट्रांसफर की चर्चा भी जोरों से गर्म हो रही थीं।

विभाग के अधिकारी शासन स्तर से ट्रांसफर सूची आने का इंतजार कर रहे थे कि रात करीब पौने ग्यारह बजे विशेष सचिव राजीव रंजन ने गौतमबुद्धनगर सीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए जबकि कुछ मिनट बाद ही बहराइच में तैनात वरिष्ठ परामर्शदाता व चिकित्साधिकारी डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर बनने के आदेश जारी कर दिए।

लखनऊ में मौसम ने ली करवट तो लोगों को मिली राहत, कम हो गई बिजली की डिमांड

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी में मौसम के करवट लेते ही बिजली की डिमांड एकदम से छह सौ मेगावाट एम्पियर कम हो गई है। 27 व 28 मई को बिजली की डिमांड लखनऊ में 2196 सौ मेगावाट के आसपास थी। उस समय गोमती नगर के लोग सबसे अधिक 192 मेगावाट एम्पियर बिजली का प्रयोग कर रहे थे। वहीं तापमान कम होते ही बिजली की डिमांड तीस मई को 1,582 मेगावाट एम्पियर हो गई। 31 मई को यही बिजली की खपत 1521 मेगावाट एम्पियर दर्ज की गई।

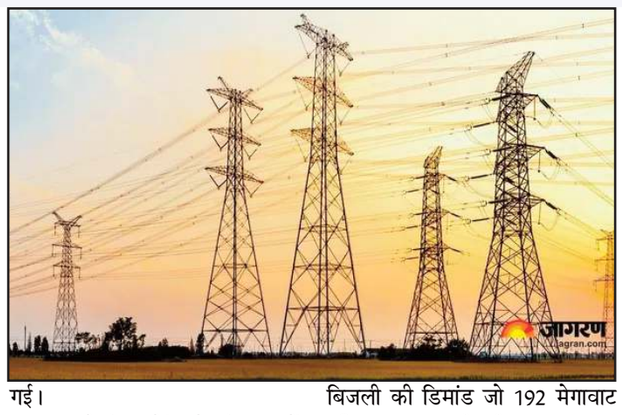

220 केवी उपकेंद्र गोमती नगर में बिजली की डिमांड जो 192 मेगावाट एम्पियर चल रही थी, वह घटकर 132 मेगावाट एम्पियर पहुंच गई। मुख्य अभियंता ट्रांसमिशन अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि मौसम अच्छा होने से बिजली की डिमांड कम हुई है।

अगर तपिश बढ़ती है तो फिर बिजली की डिमांड बढ़ने लगेगी, उनके मुताबिक अभी जून व जुलाई में बिजली की डिमांड इसी तरह घटती और बढ़ती रहेगी। बरसात में जरूर बिजली की डिमांड कम होगी। उस समय एयर कंडिशन चलना कम हो जाते हैं और उमस से डिमांड बढ़ेगी।

लखनऊ ससुराल में विवाहिता की मौत, कानपुर में मायके पक्ष ने किया प्रदर्शन, सड़क पर शव रख कार्रवाई की मांग

(जीएनएस)।

कानपुर। बाबूपुरवा की विवाहिता की लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करके सीएम योगी आदित्य नाथ से न्याय की मांग की। परिवार वालों ने लखनऊ पुलिस पर आरोपितों से मिलीभगत का आरोप लगाया। कुछ देर तक नारेबाजी कर परिवार वाले शव अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए।

बगाही निवासी 23 वर्षीय मानसी राजपूत की शादी नौ दिसंबर 2024 को लखनऊ के सआदतगंज के झव्वारन काला फाटक निवासी सागर राजपूत से हुई थी। उनके एक छह माह का बेटा भी है।30 मई को मानसी का ससुराल में फंदे पर लटका मिला था, जिस पर उसके चाचा पति और ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी।

चाचा सुनील कुमार ने बताया कि हैसियत के हिसाब से उन्होंने करीब सात लाख रुपये नकद और अन्य घरेलू सामान शादी में दिया था। इसके बावजूद पति सागर, ससुर राजेश, ननदोई अनु, ननदें बरखा और चांदनी और बुआ सास आशा अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। स्कॉर्पियो न मिलने पर मानसी को प्रताड़ित करते थे। मानसी ने कई बार फोन कर ससुराल में हो रही प्रताड़ना की जानकारी दी थी।

इसके बाद परिवार के लोग कई बार लखनऊ जाकर दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास भी करते रहे। उसे यह कहकर समझाते रहे कि नई शादी है, समय के साथ हालात सुधर जाएंगे। शनिवार को रिश्तेदारों के माध्यम से सूचना मिली थी कि उनकी भतीजी ने फांसी लगा ली है। लेकिन, ऐसा नहीं था। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालवालों ने उसकी हत्या की और फिर घटना को आत्महत्या दर्शाने के लिए उसके शव को फंदे से लटका दिया।

बाबूपुरवा थानाप्रभारी अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि मामला लखनऊ के सआदतगंज थाने से संबंधित है। मृतका उनके क्षेत्र की रहने वाली थी। परिवार वालों ने न्याय के लिए प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही परिवार वाले शव लेकर चले गए थे।

लखनऊ में कालिदास मार्ग के पास चार संविदा कर्मियों ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, आत्मदाह का किया प्रयास

(जीएनएस)।

लखनऊ, गौतमपल्ली थाना प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि चालक-परिचालकों का निजी कंपनी एसएस इंटरप्राइजेज में विलय किया जा रहा है, जिसका ये कर्मी विरोध कर रहे हैं।

अपनी मांगों को लेकर दुबग्गा डिपो में कार्यरत चार संविदा परिचालकों ने सोमवार सुबह गोल्फ क्लब चौराहे के पास खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया। पहले से मौजूद पुलिस टीम ने चारों को पकड़ लिया और थाने ले गई। पूछताछ के बाद सभी के खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई है।

एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि सुबह करीब 11.40 बजे दुबग्गा डिपो में तैनात संविदा परिचालक औरैया निवासी मुकेश सैनी, उन्नाव निवासी ज्ञानेंद्र रावत, कानपुर निवासी नितिन श्रीवास्तव और गोंडा निवासी अभिषेक सिंह बोतले में ज्वलनशील पदार्थ लेकर गोल्फ क्लब चौराहे पहुंचे।

वह लोग संविदा परिचालकों को कथित रूप से निजी आउटसोर्सिंग व्यवस्था में समायोजित किए जाने, लंबित वेतन भुगतान, कर्मचारियों के उत्पीड़न व भेदभाव पूर्ण कार्रवाई का विरोध में गोल्फ क्लब चौराहे पहुंचे थे। नारेबाजी करते हुए चोरों ने खुद पर ज्वनलशील पदार्थ डाल लिया।

आत्मदाही निरोधक टीम ने चारों को पकड़ा

गोल्फ क्लब चौराहे व उसके आसपास के वीआईपी इलाके में पहले से ही आत्मदाही निरोधक टीम की तैनाती रहती है। चारों ने जैसे ही खुद पर ज्वनलशील पदार्थ डाला, पुलिस टीम ने चारों को घेर कर पकड़ लिया। इस दौरान संविदा परिचालकों की पुलिस वालों से नोकझोंक भी हुई। सूचना मिलते ही मौके पर गौतमपल्ली पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस चारों को पकड़ कर थाने ले गई। एसीपी ने बताया कि चारों के खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, कंटेनर से भिड़ी कार, दो सगे भाईयों समेत तीन की मौत

(जीएनएस)।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार की कंटेनर से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो सगे भाईयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा

सुनील साकेत, आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार की कंटेनर से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो सगे भाईयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, सभी लोग बिहार से राजस्थान के चुरू जिले में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।। रास्ते में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उनकी कार कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।

बिहार से जा रहे थे राजस्थान

थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रास्ते में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चालक को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार से आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आधा हिस्सा कंटेनर में फंस गया और वाहन

बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी कार सवार लोग बिहार से राजस्थान के चुरू जिले में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

दो सगे भाईयों की दर्दनाक मौत

हादसे में शंकर कुमार, उनके सगे भाई सुनील कुमार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि प्रीति ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। घायल परमिता कुमारी ने बताया कि शंकर और सुनील उनके ममेरे भाई थे।

कटर से काटकर निकला बाहर

इस भीषण सड़क हादसे में करीब 5 लोग घायल हैं, जिनमें चालक मोहम्मद शोएब उर्फ सोहेब, परमिता कुमारी, पूजा कुमारी, राजीव कुमार उर्फ राजू और अयान्श शामिल हैं। ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, यूपीडा और एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। एसीपी फतेहाबाद ने बताया कि कार में फंसे लोगों को कटर से काटकर काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायलों को पहले सीएचसी फतेहाबाद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया।

लगातार 3 हादसे से खड़े हुए सवाल

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चालक को नींद आने और तेज रफ्तार को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावियों को किया सम्मानित, अभिभावकों को भी दी बड़ी सीख

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देश की मजबूत नींव यानी उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यूपी बोर्ड, सीबीएसई के साथ ही साथ आईएससी-आईसीएससी बोर्ड के मेधावियों को एक-एक लाख रुपये का चेक और टैबलेट प्रदान किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 223 मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान किया। इसमें विभिन्न बोर्ड के मेधावियों के साथ उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के छात्र-छात्राएं भी थे। लखनऊ में कार्यक्रम के साथ प्रदेश के 1459 जिला स्तर के मेधावियों को भी जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोहों में 21 हजार रुपये, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को देश के भविष्य के निमार्ता की उपाधि देने के साथ उनके माता-पिता व शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई। उन्होंने अभिभावकों को भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दो-वर्ष तीन वर्ष के बच्चों को मोबाइल पकड़ाना अनुचित है। उन्हें थोड़ा अन्य रचनात्मक विकास वाले कार्यों से जोड़िए। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि ने उन्हें गढ़ा और ज्ञान की परंपरा ने भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिलाया। आज उसी कड़ी में यह मेधावियों का सम्मान भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आप स्मार्टफोन के लिए अपने अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव न डालें। डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ें, अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दें और समाचार-पत्रों का नियमित अध्ययन करें। सोशल मीडिया पर न्यूनतम समय व्यतीत करें। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया के कम उपयोग की

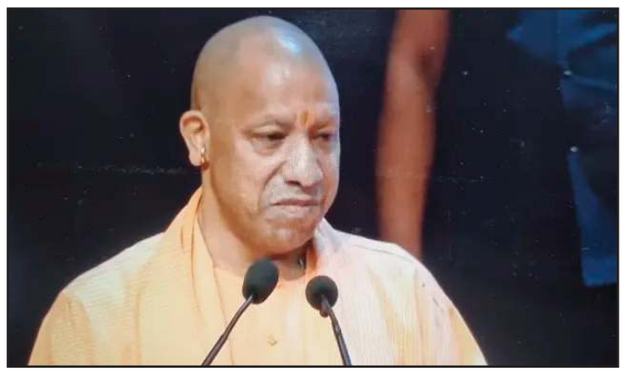

सीख दी। उन्होंने कहा कि अखबार पढ़ें, टीवी देखें तो न्यूज देखे और सोशल मीडिया का कम उपयोग करें। इसमें आप बस ज्यादातर कंटेंट और तथ्य विहीन बातों उलझेंगे। किसी भी इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। आज अति आत्म विश्वास में व्यक्ति छोटी बातों का ध्यान नहीं रखता, वही उसके विकास का बैरियर बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह उम्र ही जीवन का लक्ष्य तय करने का उचित समय है। आप सभी ग्रीष्मअवकाश का सदुपयोग करें, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालें। समय पर सोना-जागना, भोजन या भोजन का संतुलन बनाना सीखें। आप सफल हुए, अपने साथियों पारिवारिक भाई बहनों को प्रेरित करें। यह मेहनत अन्य क्षेत्रों में भी की जा सकती है, खेल, कला अनेक क्षेत्र हैं। समाज और देश के योगदान के प्रति कृतज्ञता रखें।

एक साथ 1682 छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रहे

उन्होंने कहा कि आज हम एक साथ 1682 छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रहे। विगत 9 वर्षों में हमने प्रदेश में नकल-विहीन परीक्षाएं आयोजित कराने का कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में लगभग 56 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। इनकी परीक्षाएं 14 से 15 दिनों में संपन्न हो जाती हैं और अगले 14 से 15 दिनों के भीतर उनके परिणाम भी घोषित कर दिए जाते हैं। आज से नौ वर्ष पूर्व यह संभव नहीं था, तब मेरिट-डीमेरिट का पता ही नहीं था। परीक्षा तो छात्र-छात्रों के प्रोत्साहन का माध्यम होना चाहिए। नौ वर्ष पहले तक तो परीक्षा के दौरान ठेका होना ही था, तो छात्र मेहनत नहीं करते थे। जम्मू-कश्मीर के छात्र पूर्वी यूपी के कुछ जिलों से फार्म भरते थे। उनके स्थान पर परीक्षा कोई और देता था, अब वह नहीं है।

छात्राएं मेरिट में ज्यादा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी मेरिट में छात्राएं ज्यादा आई हैं। छात्र कम आए हैं। दसवीं और बारहवीं सब में छात्राओं ने ज्यादा मेहनत की यह मेरिट बताती है कि परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के मेरिट में पिछड़ने पर चुटकी ली और कहा कि शायद छात्र अब झाड़ू-पोंछा और सब्जी लाने के साथ मोहल्ले में झाड़ू ज्यादा लगा रहे हैं।

सा विद्या या विमुक्तये

मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्ची विद्या वही है, जो हमारे जीवन में हर प्रकार की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके और उन चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा प्रदान करे, जो समाज और राष्ट्र के सामने खड़ी हैं या भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं।

नकल विहीन, शुचिता पूर्ण परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने मोबाइल के सदुपयोग पर अभिवावकों को सीख दी। उन्होंने कहा कि अभिवावक परिवार में भाई बहन, छात्र-छात्राओं से आत्मीय व्यवहार रखें। दसवीं और बारहवीं के छात्र-छात्रा किशोर वय हैं, इनसे मित्रवत सम्बंध रखें। इसके साथ ही कहा कि शिक्षक व शिक्षिकाओं का व्यवहार, उनका पहनना-ओढ़ना और आचरण बच्चों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी परीक्षा नकल विहीन, शुचिता पूर्ण सम्पन्न हुई। हमें उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों के सम्मान का अवसर मिला।

प्रदेश स्तर पर उच्च अंक प्राप्त दस मेधावियों को एक-एक लाख रुपए, टैबलेट तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। जनपद स्तर पर टॉप करने वाले दस मेधावियों को 21-21 हजार रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया। मंत्री ने कहा कि सीतापुर के बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस दौरान छात्राओं के अभिवावकों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से सम्मानित किया। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री गुलाब देवी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल भी मंच पर थीं।

आईपीएल के जमाने में फिर लौटेगा 'शीश महल' क्रिकेट टूनार्मेंट, लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर को जीवित करेंगे मोहसिन रजा

पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा ने आईपीएल के आने के बाद 2010 से बंद पड़ी इस धरोहर को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है.

(जीएनएस)।

लखनऊः एक समय देश के डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर पर जिसका दबदबा आज के इंडियन प्रीमियर लीग जैसा था, वही लखनऊ की ऐतिहासिक शीश महल क्रिकेट प्रतियोगिता फिर से शुरू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं. पूर्व मंत्री और रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा ने लखनऊ की इस अनमोल खेल धरोहर को नए सिरे से शुरू करने का बड़ा बीड़ा उठाया है.

वर्ष 1951 में शुरू हुई शीश महल क्रिकेट प्रतियोगिता 90 के दशक से लेकर साल 2000 तक देश के क्रिकेट जगत में ऐसा रुतबा रखती थी जैसा आजकल आईपीएल का क्रेज है. अप्रैल के महीने में खेली जाने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर सीधा भारतीय टीम में चयन हुआ करता था.

गावस्कर और सचिन को छोड़ सबने खेला टूनार्मेंटः अपने जमाने में केवल सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को छोड़कर बाकी देश के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेटर इस प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से खेला करते थे. मोहसिन रजा बताते हैं कि शीशमहल टूनार्मेंट हर साल गर्मियों के दौरान नवाबों के शहर लखनऊ में आयोजित किया जाता था. उत्तर प्रदेश की प्रचंड गर्मी के बीच भारत के दिग्गज अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाते थे. उस समय लाखों उत्साही घरेलू क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा स्टार्स को देखने के लिए खचाखच भरे स्टेडियम में मौजूद रहते थे.

सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाता था खेलः गर्मियों के मौसम में भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए मैचेस सुबह ठीक 6:30 बजे ही शुरू कर दिए जाते थे. जब शीशमहल टूनार्मेंट अपने चरम पर था, तब भारत के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव और बिशन सिंह बेदी सहित शीर्ष खिलाड़ियों की टोलियां भी इसकी मुरीद हो गई थीं. 1951 में शुरू हुआ शीशमहल क्रिकेट टूनार्मेंट असल में वरिष्ठ क्रिकेट प्रेमी एम. अस्करी हसन के अनोखे दिमाग की उपज थी. हसन ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर काम किया था.

धोनी को इसी मंच से मिली थी देश में पहचानः उन्होंने शुरूआत में दो-दिवसीय और तीन-दिवसीय मैचों के साथ इस भव्य कार्यक्रम की शुरूआत की, लेकिन यह समय के साथ धीरे-धीरे 50 ओवर के फॉर्मेट में बदल गया. 1970 के दशक के अंत में संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे दूर-दराज के देशों से भी नामी टीमें यहां खेलने के लिए विशेष रूप से आती थीं. इस टूनार्मेंट की इनामी राशि बहुत ज्यादा नहीं थी और टेस्ट मैच खेलने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी कोई बहुत मोटी रकम का भुगतान नहीं किया जाता था. क्लब अपने स्टार खिलाड़ियों की हवाई यात्रा और महंगे होटलों के रुकने का खर्च स्वयं वहन करते थे.

18 साल के धोनी ने जड़ा था शानदार अर्धशतकः शीशमहल टूनार्मेंट में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी सीधे नेशनल सिलेक्टर्स की पैनी नजर में आ जाते थे, जैसा काम अब आधुनिक युग में

लखनऊ में प्रीमियम अपार्टमेंट लेने का मौका, ऐशबाग स्क्वायर के 276 व पार्क व्यू अपार्टमेंट के 118 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खुला

(जीएनएस)।

लखनऊः प्रीमियम अपार्टमेंट की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) ने अपने ऐशबाग स्क्वायर और पार्क व्यू अपार्टमेंट के फ्लैटों के लिए पुनः पंजीकरण खोल दिया है. इसमें ऐशबाग स्क्वायर के 276 व पार्क व्यू अपार्टमेंट के 118 फ्लैट हैं.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर 01 जून से 30 जून तक पोर्टल लाइव रहेगा. पंजीकरण सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. इसके लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जो कि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. फ्लैटों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

उपाध्यक्ष ने बताया कि ऐशबाग में मिल रोड पर बनने वाले ऐशबाग स्क्वायर में 03 बीएचके प्लस सर्वेंट श्रेणी के कुल 384 फ्लैट्स होंगे. प्रत्येक फ्लैट लगभग 1900 वर्गफिट क्षेत्रफल का होगा, जिसकी कीमत 1.11 करोड़ से शुरू होती है. इस अपार्टमेंट के 108 फ्लैटों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा चुका है. शेष 276 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोला गया है.

इसी तरह बसंतकुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने बनने वाले पार्क व्यू अपार्टमेंट में कुल 364 फ्लैट्स होंगे. ये फ्लैट लगभग 154 एवं 195 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे, जिसमें 3 बीएचके फ्लैट की कीमत लगभग 75 लाख रुपए एवं 3 बीएचके प्लस स्टडी श्रेणी की कीमत लगभग 95 लाख रुपये से शुरू होती है. उन्होंने बताया कि पार्क व्यू के 246 फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन किया जा चुका. शेष 118 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोला गया है.

03 वर्ष में पूरा होगा प्रोजेक्ट

इन अपार्टमेंट्स का निर्माण 03 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 05 वर्ष के भीतर आवंटियों को फ्लैट का कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा. आवेदकों को आवंटन के पश्चात 36 महीने की किश्तों में पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी. वहीं, 45 से 90 दिनों में पूर्ण धनराशि जमा करने पर 6 से 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

सुविधाओं से लैस होंगे अपार्टमेंट

ऐशबाग स्क्वायर एवं पार्क व्यू अपार्टमेंट की कनेक्टिविटी और लोकेशन काफी प्राइम होगी. सोसाइटी में स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, लिफ्ट, पावर बैकअप, फ्लैटों से अधिक पार्किंग स्पेस आदि की सुविधा होगी.